<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>याचिका संख्या 2760 / 2014 (एम/एस)</u>

चरणजीत सिंह और एक अन्य.....याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती. किरण और एक अन्य.....प्रतिवादी

वादी की ओर से अधिवक्ता...श्री नीरज गर्ग।

प्रतिवादी के अधिवक्ता.....श्री पीयूष गर्ग।

माननीय न्यायमूर्ति श्री लोकपाल सिंह, जे. (मौखिक)

याचिकाकर्ताओं ने विद्वान जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा सिविल संशोधन सं. 130/2014, श्रीमती. किरण बनाम चरणजीत सिंह और अन्यमें पारित किए विद्वान विवादित निर्णय और दिनांक 24.11.2014 के आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (S.D), देहरादून द्वारा पारित मूल वाद नं. 481/2001, श्रीमती. किरण बनाम श्रीमती. रंजना (अब मृत) और अन्य मैं आदेश दिनांक 31.07.2014 को अपास्त कर दिया है।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि वादी/प्रतिवादी नं. 1 ने मूल वाद संख्या 481/2001 श्रीमती किरण बनाम श्रीमती रंजन्ना (अब दिवंगत) और एक अन्य के विरुद्ध प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधात्मक निषेधाज्ञा डिक्री के लिए दाखिल किया। प्रतिवादी नं. 1- श्रीमती रंजन्ना पर पर समन की तामील के बावजूद प्रतिवादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उपस्थित नहीं हुईं और लिखित बयान दर्ज कराया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.10.2003 को एक आदेश पारित किया कि मुकदमा उसके खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

3. एक आवेदन पत्र सं- 37-सी-2 प्रतिवादी सं- 1, श्रीमती रंजना द्वारा दिनांक 23.10.2003 दायर किया गया था जोकि दिनांक 20.04.2005 के आदेश को वापस लेने के लिए था। उपरोक्त आवेदन विचाराधीन रहने के दौरान श्रीमती. रंजना का निधन हो गया। श्रीमती रंजना के कानूनी उत्तराधिकारी, याचिकाकर्ताओं याचिकाकर्ताओं सहित, ने एक प्रतिस्थापन आवेदन दायर किया और जिसकी अनुमति दी गई, कानूनी उत्तराधिकारियों (याचिकाकर्ताओं) को 30.01.2009 को अभिलेख में लाया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.11.2011 के आदेश द्वारा आवेदन को दिनांक 23.10.2003 आदेश को वापस लेने की अनुमति दी और 30.11.2011 की तारीख तय की और याचिकाकर्ताओं को 30.11.2011 तक अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए दिए समय के बावजूद, उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल नहीं किया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 15.07.2013 पर 15.07.2013 पर अपना लिखित बयान दायर किया। लिखित बयान दाखिल करते समय विलम्ब क्षमा करने करने और लिखित बयान को अभिलेख में लेने के लिए प्रार्थना नहीं की गई थी। इस पर अभियोक्ता ने एक एक आवेदन दायर किया कि चूंकि लिखित बयान निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया है और और लिखित बयान दाखिल करने में विलम्ब क्षमा करने का अनुरोध नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर लिखित बयान को खारिज कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पर अपनी आपत्तियां दायर कीं और एक आवेदन पत्र नं. 106-सी कि वहाँ लिखित बयान दाखिल करने में कोई कोई विलम्ब नहीं है और यदि न्यायालय को पता चलता है कि लिखित बयान दाखिल करने में कोई विलम्ब विलम्ब हुई है, तो इस तरह की विलम्ब को माफ किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक दिनांक 31.07.2014 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पत्र संख्या 106-सी पर रु0 1000/- के भुगतान पर को स्वीकार कर लिया। इस कारण से कि मामले का निर्णय योग्यता के आधार आधार पर किया जाना चाहिए। हालाँकि, न तो उन्हें दिए गए समय के भीतर लिखित बयान दाखिल न करने करने पर कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया था और न ही लिखित बयान दाखिल करने में देरी की अवधि

के बारे में बताया गया था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने इस कारण से कहा कि मामले का फैसला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। आवेदन स्वीकार कर लिया और लिखित बयान रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर ले लिया।

5. , वादी ने व्यथित महसूस करते हुए, सिविल पुनरीक्षण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड राज्य राज्य द्वारा संशोधित सीपीसी की धारा 115 के तहत दी। सीपीसी की धारा 115 के संशोधित प्रावधान यहां दिए गए हैं

"**115.पुनरीक्षण**-(1) एक उच्च न्यायालय एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद या अन्य कार्यवाही में तय किए गए मामले में पारित आदेश को संशोधित कर सकता है जहां आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं है और जहां अधीनस्थ न्यायालय के पास है -

(क) ऐसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है; या

(ख) इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा; या

(ग) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया।

(2) उप-धारा (1) के से पुनरीक्षण आवेदन, जब उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है, तो ऐसे आवेदन के पहले पृष्ठ पर, मामले के शीर्षक के नीचे, इस आशय का प्रमाण पत्र होगा कि मामले में कोई पुनरीक्षण नहीं है। जिला न्यायालय के पास जाता है लेकिन मात्र उच्च न्यायालय के पास होता है या तो मूल्यांकन के कारण या क्योंकि संशोधित करने का आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

(3) उच्च न्यायालय, इस खंड के से, किए गए किसी भी आदेश को परिवर्तित या उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि-

(i) आदेश, यदि यह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता, होता, तो अंततः मुकदमा या अन्य कार्यवाही का निपटारा कर दिया जाता; या

(ii) यदि आदेश को चलने दिया जाता है, तो यह न्यायाधीश की विफलता का कारण बन सकता है या उस पक्ष को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है जिसके विरुद्ध यह किया गया है।

(4) पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष मुकदमा या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसे मुकदमा या अन्य कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई हो।

स्पष्टीकरण I-इस खंड में -

(i) "उच्चतर न्यायालय" पद का अर्थ है -

(क) जिला न्यायालय, जहाँ उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले का मूल्यांकन पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(ख) उच्च न्यायालय, जहाँ संशोधित किए जाने का आदेश जिला न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले में पारित किया गया था या जहाँ जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले में मूल वाद या अन्य कार्यवाही का मूल्य पाँच लाख रुपये से अधिक है;

(ii) "आदेश" पद में किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों में किसी मुद्दे का निर्णय करने वाला आदेश शामिल है।

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के प्रावधान प्रारंभ से पहले या पश्चात में, ऐसे प्रारंभ से पहले स्थापित मूल मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों में पारित आदेशों पर भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण III-इस धारा के प्रावधान से पहले उच्च न्यायालय में पहले से दायर किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होंगे।' अधिसूचित की जाने वाली तिथि (2006 के उत्तरांचल अधिनियम अधिनियम 1, धारा 2, W.E.F के माध्यम से।

6. अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री के अवलोकन और बलवंत सिंह के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात विद्वान जिला न्यायाधीश **(मृत) बनाम जगदीश अन्य अन्य।, एआईआर 2010 एससी 3043 और थापर बनाम एसएमई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एआईआर 2014 एससी**

897, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अवैध रूप से और बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदन को अत्यधिक विलंबित लिखित बयान को अभिलेख पर लेने की अनुमति दी है।यह अग्रेतर अभिनिर्धारित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन को अनुमति देने में कोई कारण नहीं दिया है।विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा 24.11.2014 दिनांकित आदेश को अपास्त कर दिया और संशोधन की अनुमति दी।

7. व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के से वर्तमान रिट याचिका को दिनांकित 24.11.2014 आदेश के लिए प्रमाणपत्र/रद्द करने की रिट की मांग के लिए प्राथमिकता दी है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि आदेश 8 सी. पी. सी. के नियम 1 के प्रावधान प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं।आगे यह भी तर्क दिया गया है कि आदेश 8 सीपीसी के नियम 1 के प्रावधान न्याय की उन्नति के लिए हैं और इन्हें हाथ से बनाया गया न्याय माना जाना चाहिए। उन्होंने अग्रेतर कहा कि नियम 1 आदेश 8 सी. पी. सी. के संशोधित प्रावधान मामले में लागू होते हैं।उन्होंने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी और जुर्माना रू 1, 000/- देने के कारणों को दर्ज नहीं किया ।उन्होंने अग्रेतर कहा कि पुनरीक्षण न्यायालय ने ने पूरी तरह से पुनरीक्षण की अनुमति देने में अवैधता की है; याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय का द्वार बंद नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने अग्रेतर कहा कि पुनरीक्षण अदालत को मामले को नए सिरे से तय करने करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को भेज देना चाहिए था या वैकल्पिक रूप से जुर्माने की राशि को बढ़ाना चाहिए था।याचिकाकर्ता के विद्वानअधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा जताया है - **जोलबा बनाम केशव और अन्य ने (2008) 11 एस. सी. सी. 769, सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य ने (2003) 6 एस. सी. सी. 675 में रिपोर्ट किया, श्रीमती. अंजू त्यागी और अन्र। बनाम सिविल जज (S.D)।), रुड़की और अन्य, (2011) 2 यू. ए. डी. 656 में रिपोर्ट किए गए।**

9. इसके विपरीत, के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी प्रस्तुत करेगा कि चूंकि मूल प्रतिवादी श्रीमती-रंजना ने निर्धारित समय के भीतर अपना लिखित बयान दायर नहीं किया, उस पर सम्मन पर्याप्त सेवा प्रभावित होने के बावजूद, बाद में, अदालत ने उसके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की।इसके बाद, उन्होंने 23.10.2003 दिनांकित एकतरफा आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया।जब कानूनी उत्तराधिकारियों (याचिकाकर्ताओं) को अभिलेख में लाया गया तो उपरोक्त आवेदन को 09.11.2011 स्वीकार कर लीया गया और याचिकाकर्ताओं को फिर से 30.11.2011 द्वारा लिखित बयान दाखिल करने का का समय दिया गया।यह अग्रेतर प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हें फिर से पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने एक निर्धारित अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल नहीं किया, यद्यपि उन्होंने उन्होंने एक वर्ष सात महीने और पंद्रह दिनों के अंतराल के पश्चात 15.07.2013 पर अपना लिखित बयान दाखिल करने का विकल्प चुना।प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि लिखित बयान दाखिल दाखिल करने में विलम्ब की माफी के लिए आवेदन में कोई स्पष्टीकरण या पर्याप्त कारण नहीं दिया विद्वान है।

10. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रहलाद शंकरराव के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के के एक फैसले पर अवलम्ब किया है **ताजाले और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य इसके सचिव (राजस्व) और ए. एन. आर., 2018 में रिपोर्ट किए ए (2)सुप्रीम 487, पैराग्राफ नं। फैसले का 16 भाग नीचे दिया गया हैः**

> "16. यह मामला हमें संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और अन्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425 में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, जे. विवियन बोस द्वारा गई उपयुक्त टिप्पणियों की याद दिलाता है।पीठ के लिए बोलते हुए, माननीय ने कहा कि अभिव्यक्ति की सूक्ष्म शक्ति के साथ लेखन की अपनी विशिष्ट शैली में उनके नेतृत्व ने न्यायालयों को याद दिलाया कि प्रक्रिया संहिता को पक्षकारों के अधिकारों के संदर्भ में कैसे समझा जाना चाहिए, जो उनके जीवन और संपत्तियों को प्रभावित करता है। उनके नेतृत्व ने याद दिलाया कि प्रक्रियात्मक कानूनों को यथासंभव समानताओं को दंडित करने के लिए

दंडात्मक प्रावधान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।निम्नलिखित क्लासिक मार्ग है, जिसका जिसका हमेशा पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय करने के लिए पालन किया जाता हैः

> "एक प्रक्रिया संहिता को इस रूप में माना जाना चाहिए।यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्याय को सुविधाजनक बनाने और इसके उद्देश्यों को अग्रेतर बढ़ाने के लिए बनाई गई हैःसजा और दंड के लिए एक दंडात्मक अधिनियम नहीं; लोगों को परेशान करने के के लिए डिज़ाइन की गई चीज़ नहीं।बहुत तकनीकी खंडों का निर्माण जो छोड़ देता है, इसलिए व्याख्या की उचित लोच के लिए जगह (बशर्ते किहमेशा दोनों पक्षों के लिए न्याय न्याय किया जाता है) के विरुद्ध संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए साधनों का उपयोग इसे विफल करने के लिए किया जा सके।प्रक्रिया केअनुसार कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं जिसके अनुसार पुरुषों की अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए, उनकी पीठ पीछे निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए, कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जो उनके जीवन और संपत्ति को प्रभावित करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जारी नहीं रहना चाहिए और उन्हें उनमें भाग भाग लेने से रोका नहीं जाना चाहिए। बेशक, अपवाद होने चाहिए और जहां उन्हें रूप से परिभाषित किया गया है, उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए।लेकिन मोटे तौर पर, पर, और उस परंतुक के अधीन, हमारे प्रक्रिया कानूनों का अर्थ, जहां भी उचित रूप से संभव हो, उस सिद्धान्त के आलोक में लगाया जाना चाहिए।"

11. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने ए. टी. सी. ओ. एम. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर एक अन्य फैसले पर भरोसा जताया है **टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम Y.A। चुनवाला चुनवाला एंड कंपनी एंड अदर्स ने (2018) 6 एस. सी. सी. पर रिपोर्ट की** 239, जिसमें सी. पी. सी. के आदेश 8 के नियम 1 के उद्देश्य पर चर्चा की गई है।प्रासंगिक अनुच्छेद एन. ओ. एस.। 20, 21 और 22 यहाँ नीचे निकाले गए हैं:

"20. यह प्रावधान कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि'नब्बे दिनों के बाद नहीं होगा' शब्द उस समय के बाद लिखित बयान को प्रतिग्रहण प्रतिग्रहण करना करने की न्यायालय की शक्ति को नहीं छीनते हैं के बाद यह भी माना जाता है कि प्रावधान की प्रकृति प्रक्रियात्मक है के बाद यह मूल कानून का हिस्सा नहीं है।साथ ही, इस न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि समय मात्र असाधारण रूप से कठिन मामलों में ही बढ़ाया जा सकता है। हम सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ, (2005) 6 एस. सी. सी. 344 के मामले से निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

> "21. ..... आदेश 8 नियम 10 में कोई प्रतिबंध नहीं है कि नब्बे दिनों की समाप्ति के अग्रेतर का समय नहीं दिया जा सकता है।अदालत के पास "मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देने की व्यापक शक्ति है जो वह वाद में समझे।"स्पष्ट रूप से, इसलिए, लिखित विवरण दाखिल करने के लिए 90 दिनों की ऊपरी सीमा प्रदान करने वाले आदेश 8 नियम 1 1 का प्रावधान निर्देशिका है।ऐसा कहने के बाद, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का आदेश नियमित रूप से नहीं किया जा सकता सकता है।समय मात्र असाधारण रूप से कठिन मामलों में ही बढ़ाया जा सकता है।समय बढ़ाते समय, यह ध्यान में रखना होगा कि विधायिका ने 90 दिनों की ऊपरी समय-सीमा तय की है।समय बढ़ाने के लिए न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग इतनी बार और नियमित रूप से नहीं किया जाएगा कि आदेश 8 नियम 1 द्वारा निर्धारित अवधि को रद्द कर दिया जाए।"

21. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी पर तीस दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल नहीं करने के लिए एक वैध कारण का अनुरोध करने और संतोषजनक रूप से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होती है।जब यह एक आवश्यकता है, तो क्या यह 5 साल से अधिक की विलम्ब क्षमा करने का आधार

हो सकता है, भले ही इसकी गणना वर्ष 2009 से की गई हो, मात्र इस कारण से कि 2009 तक सम्मन देना का रिट जारी नहीं किया गया था?

22. हम विलम्ब को माफ करने में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस तरह के तर्क के साथ खुद को मनाने में विफल रहते हैं, जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 1 के प्रावधानों और इसके पीछे की भावना की अवहेलना होती है।उच्च न्यायालय का यह तर्क कि देरी को 'अधिकारों और इक्विटी को संतुलित करके' माफ कर दिया गया था, दूर की कौड़ी है और इस प्रक्रिया में, लिखित बयान दाखिल करने में असामान्य देरी को संबंधित कारक को संबोधित किए किए बिना माफ कर दिया जाता है। क्या उत्तरदाताओं ने इस तरह की देरी के लिए उचित और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था । उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से स्पष्ट रूप से गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।इसमें कोई संदेह नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 1 के प्रावधान प्रकृति में प्रक्रियात्मक हैं और इसलिए, इसलिए, न्याय के सहायक हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रतिवादी को देरी के लिए लिए ठोस कारण बताए बिना, लिखित बयान दाखिल करने में जितना चाहे उतना समय लेने का अधिकार है और उच्च न्यायालय को यांत्रिक रूप से उसे माफ करना होगा।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायालय का मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को बिना बिना कोई कारण बताए अवैध रूप से अनुमति दी थी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तरांचल राज्य और एक अन्य बनाम सुनील कुमार वैश्य और अन्य का मामला 2011 में दर्ज किया गया था। (8) एस. सी. सी. 670 ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिक निर्णयों को सैद्धांतिक रूप से तर्कपूर्ण होना चाहिए और न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता सिद्धान्त से इसके तर्क की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।उचित तर्क एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे कार्यसाधकता के लिए बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने के

के लिए याचिकाकर्ताओं के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है और प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान और आवेदन को अवैध रूप से अनुमति दी गई है।इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुप्त आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। बिना कोई कारण बताए।याचिकाकर्ता उनकी निष्क्रियता, ढिलाई का लाभ नहीं उठा सकते और उचित समय के भीतर लिखित बयान दाखिल न करना उनकी गलती है। मुझे विवादित निर्णय और आदेश में कोई अवैधता, विकृति और अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं मिली।रिट याचिका खारिज की जा सकती है। इसे खारिज किया जाता है।

14. इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि मूल वाद वर्ष 2001 में दायर किया गया था, विद्वान विचारण न्यायालय को वाद शीघ्रता से तय करने का प्रयास करेगा और मामले में अनावश्यक स्थगन से बचाएगा।

15. वाद व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं।

ह0

(लोक पाल सिंह, जे.)

23.10.2018

बलवंत